







मप्र के ऐतिहासिक नगरी में  
निकली विशाल तिरंगा यात्रा  
सीएम मोहन ने किया नेतृत्व



गवालियर। मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक नगरी गवालियर में तिरंगा यात्रा निकली गई। राजभासा विजयराजे सिंहिया चौराहे से विशाल यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। सीएम डॉ. यादव खुले संग्राम सेनानियों की धरती गवालियर में आयोजित हुई देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

## निर्यात में मप्र की रैकिंग में सुधार अहम संकेत : भाजपा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के उपायक जीतू जिराती ने विदेश को होने वाले नियर्यात में मध्यप्रदेश की रैकिंग 15 से 11वें स्थान पर पहुंचने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धि करार देते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के कार्यकाल में मध्यप्रदेश तेजी से विकास और समृद्धि की राह पर कदम बढ़ा रहा है तथा देश को उनियां की अधिक मध्यसंक्षिक बनाने में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिराती ने कहा कि उद्योगों के क्षेत्र में हासिल इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार प्रदेश के सर्वाधिक विकास और नाप्रियों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है और अब सरकार के इन प्रयासों के परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं।

## राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार किया नए आयोग का ड्राफ्ट

# अब परिसीमन आयोग तैयार करेगा मप्र में चुनाव की जमीन

**निकायों  
व पंचायत  
चुनाव के लिए  
आरक्षण का  
जिम्मा भी  
मिलेगा**

दोपहर मेट्रो, भोपाल।

मप्र ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए यदि परिसीमन आयोग बना जाता है तो चुनावी व्यवस्थाओं में बदलाव आ जाएगा। नगर निगम के नेतृत्व, नगर पालिका-परिषद के अध्यक्ष, पंचायत में पंच-संघ, जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और वार्डों के परिसीमन का जिम्मा आयोग का एहसान। दृष्टिअस्त बाल ने राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से राज्य परिसीमन आयोग बनाने की सिफारिश की है। अभी नगरीय निकायों के लिए ये काम नगरीय प्रशासन विभाग और पंचायतों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करता है।

### परिसीमन आयोग को अधिकार देने की सिफारिश

जनकारी के मुताबिक आयोग ने अपने ड्राफ्ट में केंद्रीय परिसीमन आयोग की ही तरफ राज्य परिसीमन आयोग को भी अधिकार देने की सिफारिश की है। इसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पुरुषांन, परिसीमन और परिसीमन का अधिकार देने की विवरणीय की जिक्र किया है। बाला जाता है कि आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद में ड्राफ्ट में कहा गया है कि परिसीमन व आरक्षण से संबंधित आयोग के किसी भी फैसले को आरक्षण नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का जिम्मा है। जिला कलेक्टर के जरिए वार्डों का आरक्षण व आवास विभाग को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। केंद्रीय आयोग के फैसले को भी एवं चुनौती नहीं देने का प्रावधान है।



**कलेक्टर कराते हैं वार्ड का परिसीमन**  
उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था में नगरीय निकायों के लिए वार्डों का परिसीमन और पर्दों का आरक्षण नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का जिम्मा है। जिला कलेक्टर के जरिए वार्डों का आरक्षण व आवास विभाग को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी विवरणीय की जिक्र किया है। बाला जाता है कि आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद में ड्राफ्ट में कहा गया है कि परिसीमन व आरक्षण से संबंधित आयोग के किसी भी फैसले को आरक्षण नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का जिम्मा है। जिला कलेक्टर के जरिए वार्डों का आरक्षण व आवास विभाग को कोर्ट का फैसला जाता है। वहीं पंचायतों के दरवाजा खटखाते हैं।

### मुख्यसचिव स्तर के अफसर को कमान

यदि मप्र में आयोग अस्तित्व में आया तो एकट के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक वह केंद्रीय आयोग की तरह काम करेगा। 31वीं केंद्रीय आयोग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करता है। राज्य का आयोग नगरीय निकायों और वार्डों की सीमा का निर्धारण करता है। इसके साथ ही महापौर, अध्यक्ष और वार्डों के अधिकार की प्रक्रिया भी आयोग की जिम्मेदारी होगी। राज्य परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य सचिव रैक्ट के किसी अफसर को बनाया जा सकता है। साचेव स्तर से रिटार्न तीन अफसर आयोग के सदस्य रहेंगे। संवाद शर्त वहीं रहेंगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की है।

### इस व्यवस्था के कई खट्टे

ड्राफ्ट मप्र के चुनाव कार्य व परिसीमन प्रभारी जैपै धनोपायी ने कहा है— मप्र में पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं रही है। निकाय की चुनाव की प्रक्रियानामनीरीय प्रशासन विभाग के जरिए होती रही है। सरकार जो नई व्यवस्था लाने की कोशिश में वह, हर समांतरोंयोग्य आपातकात और आकांक्षिक जिलों सीमी, सिंगरारैली, पाली, टीकमगढ़, छतरपुर और डिल्लीरी में भरे गए हैं।

## 400 सामुदायिक रसायन अफसरों की नियुक्ति

# दूरदराज के इलाकों में तीस मिनट की दूरी पर होंगी रसायन सुविधा

दोपहर मेट्रो, भोपाल।

मप्र के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाली आबादी को अब अपने घर से अधिकतम 30 मिनट की दूरी पर प्राथमिक रसायन सेवाएं देने की कवायद शुरू की गई है। राष्ट्रीय रसायन मिशन (एनएचएम) ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 400 से अधिक सामुदायिक रसायन अधिकारियों (सीएचओ) की नियुक्ति की है। खास बात यह है कि ये पहले उच्च प्राथमिकता और आकांक्षिक जिलों सीमी, सिंगरारैली, पाली, टीकमगढ़, छतरपुर और डिल्लीरी में भरे गए हैं।



आरोग्य मदिरों में की जा रही है। इनकी नियुक्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवस्था देखभाल, बाल व किशोर स्वास्थ्य, संचारी-असचारी रोग प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल, मुख, दंत, नेत्र व ईंटीटी रोगों के साथ आपातकालीन सेवाएं भी नजदीकी में उपलब्ध होंगी। राज्यभर में स्थापित आयोग्यान आयोग मदिरों में 10 तक 20 की जिलों के मुताबिक एक एनएचएम अधिकारियों के अनुसार, इन छह जिलों में कुल 415 सामुदायिक रसायन अधिकारियों की पदस्थापना आयोग्यान निशुल्क दो जाती हैं।

### आयोजित किए जाएंगे रसायन वर्तक कार्यक्रम

इसके अलावा, योग दिवस, पोषण दिवस जैसे स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें से 10,189 केंद्रों पर सीएचओ की आवायकता थी, जिनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा पद अब भर चुके हैं। हाल ही में चर्चनामित सीएचओ को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पदस्थापना स्थल के विकल्प चुनने का अवसर दिया था। अब दस्तावेज स्थलांतिकरण के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

## 24 जिलों में कलेक्टर लेंगे सलामी सीएम भोपाल में करेंगे झंडा वंदन, मंत्रियों को मिले जिले

दोपहर मेट्रो, भोपाल।

राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर मंत्रियों के लिए ध्वजारोहण करने जिलों का आवान्त कर दिया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें ध्वजारोहण करेंगे। डिली सीएम जगदीश देवजड़ा जबलपुर और राजेंद्र कुमार सुरुल शहरांडोल में ध्वजारोहण करेंगे। 31 जिलों में सीएम और मंत्रियों के अलावा 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। अभी विधानसभा अध्यक्ष नेट्रो दिवस पर तोमर को भी योनी जिले के साथ ध्वजारोहण करेंगे। इंदौर, धार, झावुआ, पत्ता, टीकमगढ़, निवाड़ी, सारांग, उड़ैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगरा भालावा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुरु, अशोकनगर, दत्तात्री, कटीपी, छिंडवाडा, सिवनी, रीवा, सिंगरारैली एवं उमरिया जिले में संबंधित जिले के कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे।

### विरास सारंग खरणोन में करेंगे ध्वजारोहण

विजय शाह रतलाम, करण सिंह मुनैना, उद्यप्रताप सिंह बालाघाट, संपत्तिया उड़ैके मंडल, तुलसी सिलवट बुराहनपुर, निर्मला भूमिका मंदसोर, गाविंद सिंह राजपूर नरसिंहपुर, विधास सारंग खरणोन, प्रयुम्न सिंह पार्दुना, कृष्णगांग शिवोर, इंदौर सिंह देव, चैत्र्य ध्वजारोहण राजगढ़ और ध्वजारोहण करेंगे। इंदौर, धार, झावुआ, पत्ता, टीकमगढ़, निवाड़ी, सारांग, उड़ैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगरा भालावा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुरु, अशोकनगर, दत्तात्री, कटीपी, छिंडवाडा, सिवनी, रीवा, सिंगरारैली एवं उमरिया जिले के कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे।

पटवारी ने मीडिया से कहा कि संविधान की सबसे बड़ी ताकत जिला

**P**

वर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यशैली कोई आज या कल से ही चर्चा में नहीं है या किसी एक दो मामले में उसके एकशन से चर्चा में नहीं है बल्कि लंबे समय तौर पर यह सवाल ज्यादा तीखा है लेकिन उसकी भूमिका पर यदि अदालतें बार बार टिप्पणी कर रही हैं तो ऐसी ही

समझना चाहिए कि उसे अपने स्तर पर कार्यशैली को ज्यादा प्रभावी और विश्वसनीय बनाना होगा। राजनीतिक दलों का तो सीधा ही आरोप है कि ईडी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करती है। वहीं उच्च न्यायालयों से लेकर शीर्ष अदालत ने भी निदेशालय को कई बार सवालों के कठउते में खड़ा किया है। यह अफसोसाकार है कि ईडी की जांच में आरोपी बनाए गए लोग दोषी सिद्ध न होने पर भी महाने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि धनशोधन रोकथाम कानून का दुरुपयोग कैसे और क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। इसीलिये चार दिन पहले

## मुश्किलों से भरे रक्त में हमारे सामने दो रास्ते होंगे - एक सही और एक आसान।

- जे.के. रोलिंग

### निशाना

आग ना लगाओ !



- कृष्णदेव राय

व्यर्थ की इन बातों को।  
मुझ ना लगाओ ॥  
और भी हैं मुझे ॥  
उनको राह लिखाओ ॥  
शांति और खुशहाली में ॥  
आग ना लगाओ ॥  
क्या सही क्या गलत ।  
जन जन तक पहुंचाओ ॥  
तूत देने से बचो ।  
बातें व्यथ बाली ॥  
बन रहा है कब से ।  
पुलाव बस खायाली ॥  
हवा हवाई के केवल ।  
है होता नुकसान ॥  
देर हो रही होने में ।  
पुनः विराजमान ॥

### आज का इतिहास

- 2000 : रूसी नौसेना की पनडुब्बी कुर्कुट एक सैन्य अस्थाय के द्वारा नौसेना सागर में विस्फोट और डूब गई और अपने पूरे 118 व्यक्तियों के दल को मार डाला था।
- 1994 : मेजर लीप बेसबॉल खिलाड़ी 1994 की विश्व शूरुवात को रुद्ध करने के लिए मजबूर हुई थे।
- 1992 : कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (एनएफटीए) के लिए बातचीत पूरी करने की घोषणा की थी।
- 1985 : जापान एयरलाइंस प्लाईट 123 जापान के गुमा प्रैंकिंगर में ऑसुताका रिज में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसमें 520 की मौत हो गई।
- 1981 : आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर जारी किया गया था।
- 1964 : देश की जातिवादी नीतियों के कारण दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- 1960 : नाको का पहला सफल संचार उपग्रह इको 1 ए

# संसद में मार्शल द्वारा जबरन बाहर निकालने की मिसालें

## ■ आलोक मेहता

**राज** य सभा में कांग्रेस के विषय नेता मलिकार्जुन खगोरे ने राजसभा के अंदर ( वेल ) में केंद्रीय औद्योगिक सुक्ष्मा बल ( छहसूर्य ) के कर्मचारियों की तैनाती को अस्वीकृत आपत्तिजनक बताया। 2-5 अगस्त तक राजसभा में विषय लगातार इस मुद्दे पर हांगामा करता रहा, एवं मानसन सभा में कई दिनों तक विषयी सांसद प्रदर्शन जारी रखा। उपसभापति हरिवंश ने स्पष्ट किया कि इस सुरक्षा बल के कर्मचारी की तैनाती सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सभामंडल सुक्ष्मा हेतु की गई है, और +राजसभा का संचालन गृह मंत्रालय या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में सुक्ष्मा बल की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है; वे +संसद की ही सुरक्षा व्यवस्था का अंग हैं, और कबालद सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हैं। केंद्रीय संसदीय मत्री किरेन रिजिकू ने कहा कि ये निर्णय सभापति द्वारा ही लिए गए थे, ये शांति बनी रहे। उन्होंने विषय की आपत्तियों को +गलत तथ्यों पर आधारित भ्रामक बयानबाजी- बताया। तथ्य यही है कि 13 दिसंबर 2022 के लोकसभा के अंदर बाहरी लोगों के घुसने के हांगमे के बाद, स्पष्ट संसद की सुक्ष्मा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुक्ष्मा बल को सौंप दी गई। मई 2024 से संसद सुरक्षा बल की भूमिका बढ़ी और अंदरूनी कार्यक्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई।

इस बार के हांगमे और विवाद पर पुरुष संसद में 1971 , 1973 , 1974 के दौरान प्रमुख सोशलिस्ट नेता राजनारायण सभापति के आदेश पर मार्शलों द्वारा कई बार बाकायदा कन्धों पर उतारकर सदन से बाहर निकाले जाने की घटनाएं घट आईं। मैं 1971 से प्रत्कार के रूप में संसद की कार्यवाही देखना और लिखाता रहा हूँ। उस सभाय संसद की कार्यवाही की टीवी प्रसारण नहीं होता था। संसद के कर्मचारी विवरण शर्ट हेंड से लिखर किरकॉट करते थे। तब एजेंसी के संवाददाता होने से मुझे लगातार सदन की प्रेस दीर्घी में बैठा होता था। इसलिए उन बातों का ध्यान है। राजनारायण द्वारा बार-बार राजसभा में आदेलानात्मक, आक्रामक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्याप्त आई है। वह सभापति की चेयर के सामने नीचे धरना देकर बैठ जाते थे। तब सदन के नियमों की अवहेलना के कारण उन्हें सभापति के आदेश पर मार्शलों द्वारा कई बार बाकायदा कन्धों पर उतारकर सदन से बाहर निकाला गया। जहाँ तक मुझे सरण है उस समय सभापति उप राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक होते थे। राजनारायण एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे, जो कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यशैली के प्रबल विवादी था। उन्होंने बार-बार संसद में नियमों को चुनौती दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अधिकारियों की स्वतंत्रता के मुद्दे उठे। उनके मामलों ने यह सवाल भी उठाया कि कब विरोध जायज होता है और कब वह संसद की गरिमा को देप पूछता है। उनके बाद एवं बाहर संसद में नियमों को चुनौती दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अधिकारियों की स्वतंत्रता के मुद्दे उठे। उनके मामलों ने यह सवाल भी उठाया कि कब विरोध जायज होता है

याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया और कम दोषसिद्धि दर के लिए प्रभावशाली आरोपियों की टालमटोल की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। अगर इस संस्था की छाव इस कदर नकारात्मक बन रही है, तो इस पर उसे सोचने की जरूरत है। गौरतलब यह है कि शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज पर कोई पिछले महीने भी कहा था कि ईडी सभी हैं दैर कर रही है। यह गंभीर स्थिति है कि न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपी जेल से बाहर आ जाते हैं। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय न तो अपनी जांच पूरी कर पाता है और न ही उनके खिलाफ आरोप सिद्ध कर पाता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर ईडी के पास किसी आरोपी

को गिरफ्तार करने के लिए मजबूत आधार होता है तो दोषसिद्धि की दर दस फौटां से भी कम क्यों है। इस पर चिंता जाती है कि उचित सवाल किया है कि अगर आरोपी बड़ी हो जाते हैं, तो इसका भुगतान कौन करेगा। यह बेकसूर नामियों की स्वतंत्रता का भी सवाल है। माना जाना चाहिए कि ईडी की छाव पर अगल लगातार प्रश्न उठाए जाएं, तो इसका निवारण अब उसे उपरी पर करना होगा। इस संदर्भ में ईडी को शीर्ष अदालत की इस नीति के बारे में यह सवाल भी है कि राजनीतिक तौर पर देश की कई सकारी संस्थाओं की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं बल्कि यह सीधी होते जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के आरोप या आशका पुरानी ही हैं कि इन एजेंसियों का %इस्तेमाल% होता है, मगर आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता और तीखा होता रहे तो सिर्फ सुधार व आत्मचिंतन ही जरूर होता है।

और कब वह संसद की गरिमा को लेप पहुंचाता है। उन्होंने बार-बार संसद में नियमों को चुनौती दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे उठे। उनके मामलों में यह सवाल भी उठाया कि कब विरोध जायज होता है और कब वह संसद की गरिमा को लेप पहुंचाता है।

राजसभा और लोकसभा में मार्शलों का प्रयोग केवल अल्पाधिक असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जब सदन की गरिमा, सुरक्षा और कार्यवाही को बाहर रखने में बाधा उत्पन्न होती है। भारतीय संसदीय झिलास में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हैं जब सांसदों को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शलों का सहारा लिया गया।

लोकसभा में 1989 में जब बोफोर्स तोप घोटाले पर विषय ने हांगामा करता रहा, एवं मानसन सभा में कई दिनों तक विषयी सांसद प्रदर्शन जारी रखा। उपसभापति हरिवंश ने स्पष्ट किया कि इस सुरक्षा बल के कर्मचारी की तैनाती सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सभामंडल सुक्ष्मा हेतु की गई है, और +राजसभा का संचालन गृह मंत्रालय या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी बाहरी कोई कार्यवाही की तैनाती नहीं है, वे +संसद की ही सुरक्षा व्यवस्था का अंग हैं, और कबालद सदन की कार्यवाही देखना के लिए हैं।

महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी और राजद के सांसदों ने भारी विरोध किया। 7 सांसदों को



मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया। यह एक अलंतर दुर्लभ घटना थी जब उन्हें सांसदों को एकसाथ राजसभा से निकाला गया। मार्शल संसद भवन की सुक्ष्मा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं। सभापति ( राजसभा ) या अध्यक्ष ( लोकसभा ) के आदेश पर ही को विसर्जित करने से बाहर निकाल सकते हैं। अमांतर पर सदस्य को पहले नाम लेकर चेतावनी दी जाती है, उसके बाद भी नियम तोड़ने पर सर्पेंड या सदन से बाहर करने का आदेश दिया जाता है।

छहसूर्य को स



# हाईकोर्ट ने एविएशन मिनिस्ट्री और निजी विमान कंपनियों को दी चेतावनी उड़ानों में सुधार नहीं हुआ, तो जबलपुर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, अन्य उड़ानों पर भी लगाएंगे रोक

जबलपुर, एजेंसी।

हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिओजनल बैंच में हुई सुनवाई में जबलपुर से उड़ानों की संख्या घटने और सीधी फ्लाइट्स की कमी पर संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख दिखाया गया। कोर्ट ने एविएशन मिनिस्ट्री और निजी विमान कंपनियों को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि उड़ानों में सुधार नहीं हुआ, तो जबलपुर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर और नवालपुर से भी उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी।

एयरलाइन कंपनियों की ओर से भी बस इतना कहा गया कि वे अभी इस पर विचार कर रही हैं। कोर्ट ने इस रखें को गभीर लापवाही मानते हुए टिप्पणी की न कोई काम हो रहा है, न कोई असरदार पत्राचार। अगर यह स्थिति बनी रही तो हम



एयरपोर्ट हो बंद करा दग। सुनवाई के दौरान सचिवाकार ने फिर वही तर्क दोहराया कि जबलपुर में उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए जो भी ठोस कदम उठाए गए हैं, उनकी जानकारी कोटि में ही जाए। इसके साथ ही उहें निर्देश दिया गया कि जो यात्री जबलपुर से दिल्ली और मुंबई केनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं, उन सभी का यात्री डाटा पेश किया जाए और यह भी हलफनामा दिया जाए कि यह दोपहर की फ्लाइट को सुबह या शाम में शिफ्ट करना संभव है। यह सारा कर्मशाल डाटा सील बंद फ्लाइट में कोई में जमा करना होगा। बैंच ने एविएशन डिपार्टमेंट के पर्दशनाल चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि अब तक जबलपुर में उड़ानें 28 अगस्त 2025 तक यह करें।

## इंडिगो बताए... जबलपुर में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं

हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस संचालित करने वाली इंटररोल एविएशन लिमिटेड को आदेश दिया कि जबलपुर में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए जो भी ठोस कदम उठाए गए हैं, उनकी जानकारी कोटि में ही जाए। इसके साथ ही उहें निर्देश दिया गया कि जो यात्री जबलपुर से दिल्ली और मुंबई केनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं, उन सभी का यात्री डाटा पेश किया जाए और यह भी हलफनामा दिया जाए कि यह दोपहर की फ्लाइट को सुबह या शाम में शिफ्ट करना संभव है। यह सारा कर्मशाल डाटा सील बंद फ्लाइट में कोई में जमा करना होगा। बैंच ने एविएशन डिपार्टमेंट के पर्दशनाल चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि अब तक जबलपुर में उड़ानें



बढ़ाने और बड़े शहरों से केनेक्टिंग्सी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए, उसका विस्तृत हलफनामा पेश करें। साथ ही उहें अगली सुनवाई में वीडियो कॉफेस के जरिए मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 तक यह करें।

## 20 गांवों से उमड़ा सैलाब, बोल बम के जयकारों से गुंजा शहपुर



बुरहानपुर। शहपुर और नेपानगर प्रखंड में धार्मिक अस्था का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके का माहौल शिवमय कर दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिला ब्रह्मपुर के बैनर तले, ग्राम साड़स ते गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक और मानसगंगा से शहपुर नगर प्रमण करते हुए विशाल कावड़ यात्रा निकली गई। सुबह से ही गांव-गांव से भगवान वर्षों में सजे महिला-पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग कावड़ हाथ में लिए बोल बम के जयकारे लगाते हुए जुटने लगे। करीब 20 गांवों से एए 1500 से अधिक कावड़ियों यात्रा में दुम्लिंग हुए। यात्रा जैसे ही मार्ग पर बढ़ी, श्रद्धालूओं ने जग-जगह सड़क पर पुष्प वर्षा और फलाहारी जलपान की व्यवस्था कर भोले के भक्तों का खागद किया। यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बड़ने भी कदम से कम मिलाकर चली। भगवान पालना था और हर-हर महादेव के उद्घाटन से उहोंने माहौल को और ऊर्जावान बना दिया। छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी नहीं कावड़ के साथ उस्थान से चलते रहे। कार्क्रम में जिला मंत्री युवराज पाटिल, प्रखंड मंत्री, संयोजक समेत जिले और प्रखंड के कई पदाधिकारी, संयोजक और बड़ी संख्या में बजरंगी कार्यकारी मौजूद रहे। आयोजन की जानकारी प्रचार-प्रसार प्रमुख दिनेश राठोड़ ने दी।

## मैगी खिलाने के बहाने छह साल की मासूम के साथ किया घिनौना कृत्य

बड़वानी। मैगी खिलाने के बहाने एक युवक ने 6 साल की मासूम के साथ घिनौना कर्त्तव्य किया था। जिसका आदिवासी संगठनों ने जकर विरोध किया। पुलिस ने विरोध के बाद दुकर्कम करने वाले युवक के दबोच लिया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कर्म करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को समझाया कि इसे किसी उत्सव के तौर पर न देखा जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सासन की ओर से अतिरिक्त महाधिकरका हरप्रीत सिंह रुपराह और पैनल अधिकरका आकाश मालपानी ने पक्ष रखा।

## अनियंत्रित स्कॉर्पियो दीवार तोड़कर घुसी, मौके पर ही पांच लोगों की मौत

### अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा

जिले से भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, जिले के रामनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो मोटरसाइकल को जारीदार टक्कर माने के बाद भाग रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा गयी। हादसे में बाइक चालक और उसके साथी समेत स्कॉर्पियो सवार तीन यात्री कुल 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी यायलों को इलाज के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लागाया गया है।



लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, स्कॉर्पियो में सवार होकर 7 लोगों को तोमा से बेलिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में स्कॉर्पियो ने सामने से आई एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अपनी यात्री और उसके साथ बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई। अहिंसा इलाज के लिए सभी यायलों को इलाज के लिए सवार दोनों युवकी की पहचान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्षरथियों की माने तो हादसे के बाद स्कॉर्पियो

चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन बाहन अनियंत्रित होने से सड़क से उत्तरकर समीप के घर में जा गयी। एसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की भी मौत हो गई। मृतकों में कार में सवार शुभम अहिंसा की यात्रा थी। अदालत ने जिले के बाद से बेलियों में भाग रही थी। लोगों को अपने घर रहने के लिए बाइक को आगे ले जाना अस्तित्व भरती किया जा सकता है। इस घटना की जानकारी लगाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मृतकों में एक साख्सी पर हाथ लगाते ही जानकारी दी गई है।

लोगों

</div



